

## -: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 138/2022

उनवान

सांवरलाल पुत्र भंवरलाल जाति अहीर निवासी पुलिस थाने के पीछे जिलावडा रोड, खेडा चौराहा, ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद

— प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

— अप्रार्थीगण :- 1 जरियें राज. पैरोकार,

2 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :-

दिनांक :- 25/6/22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के बंकिंग खसरा नम्बर 4876 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 5202 रकबा 4.71 में से 0.56 है० की भूमि पर प्रार्थी का पुरतैनी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख अनुसार सम्बत् 2048, 2049, 2050, 2052, 2053, 2054 से प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि अजमेर जिले में 15.06.1958 को लागु हुआ था, की धारा 15 के अनुसार भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर कब्जा होने के कारण धारा 15 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त सम्पदा राजस्व अभिलेख में सिवायचक होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का कब्जा लगातार नहीं होने के कारण वाद खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। धारा 80 सी.पी.सी. की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं की गयी है। अतः आवेदन पत्र सब्यय खारिज किया जावे।


अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी को कब्जा आज दिनोंक तक चला आ रहा है। प्राधिकरण को दिनांक 12.09.2022 को धारा 74 अजमेर विकास प्राधिकरण आिनियम 1913 का नोटि दिया गया था।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं।

—2



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद (अजमेर)

**प्रथम दृष्टया मामला :-**

ग्राम श्रीनगर के वॉर्किंग खसरा नम्बर 4876 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 5202 रकबा 4.71 में से 0.56 है० की भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख में सिवायचक थी। उक्त आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा कभी भी प्रार्थी/पूर्वज के नाम खातेदारी पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद में कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है, जबकि सिवासचक आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 2 आराजी मुतनाजा का रिकार्डर्ड खातेदार है। जिसे बिना किसी टोस आधार के पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध नहीं होता है।


2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थी/पूर्वज के नाम पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने को कोई प्रमाण नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध नहीं है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्ध नहीं होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होंगे।

**आदेश :-** श्रीनगर के वॉर्किंग खसरा नम्बर 4876 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 5202 रकबा 4.71 में से 0.56 है० की भूमि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

